ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Infrastructure of Dr. Bhimrao Babasaheb Ambedkar University

*441. SHRI R.P. GOENKA: Will the Minister of HUM AN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Dr. Bhimrao Babasaheb Ambedkar University, Lucknow, established in 1989 and declared a Central University in 1996, has only 175 students on rolls and does not have even approach roads, entry gates etc.;

(b) if so, the reasons for the apparent neglect and languishing of the Central University; and

(c) the steps being taken to make the University functional for better utilisation of the infrastructure and the facilities created?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLIMANOHAR JOSHI): (a) to (c) According to the information furnished by the Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BBAU), Lucknow, its academic programmes were launched only in 1997 and the University has 159 students on its rolls during 1999-2000. A motorable approach road to the University and the entry gates exist. The Central Government has provided Rs. 20.98 crores to this University since its inception for maintenance and development.

श्री आर पी गोयनका : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इन्होंने 20 करोड़ रूपए पिछले तीन-चार सालों में जरूर खर्च किए हैं लेकिन नैट रिजल्ट क्या रहा? वहां पर स्टूडेंट नहीं आते हैं और यूनिवर्सिटी की साइन बोर्ड तक नहीं लगा है । इस युनिवर्सिटी को पॉपुलर करने के लिए सरकार ने क्या रुख अपनाया है? इसी के साथ मेरा दूसरा सवाल हैं, उनके नाम पर बनी यूनिवर्सिटी के प्रति इतनी बेजारी देखकर मन में कुछ दुख होता है। यह पहला सक इंस्टांस नहीं है, देश में और भी कई जगह नेशनल लीडर्स के नाम पर इंस्टीट्यूशन्स बने हैं उनके प्रति सरकार ने डिसरिस्पेक्ट दिखाई है, बेजारी दिखाई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सरकार की पॉलिसी है या ऐसा गलती से हो गया है?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : सभापतिजी, इस विश्विद्यालय में जब से शैक्षिक कार्यक्रम शुरू हुआ है, 1997 से, बराबर छात्रों की संख्या बढ़ रही है। 1997-98 में कुल 130 छात्रों की भर्ती की क्षमता थी लेकिन 118 छात्र ही आए । 1998-99 में यह संख्या 170 थी जिसमें 163 छात्र आए, 1999-2000 में 168 में से 159 छात्र आए और 2000-2001 में अभी तक 168 छात्रों में से 159 आ चुके हैं तथा भर्ती की प्रक्रिया चल रही है यह कहना गलत है कि इस विश्वविद्यालय में लोग नहीं

आते। लगभग दो सौ छात्र यहां से पास होकर निकल चुके हैं। एनवॉयरमेंट साइंसस, इन्फोर्मेशन साइंस, हार्टिकल्चर, सेरिकल्चर, ह्यूमन राइट्स, कम्प्यूटर सोफ्टवेयर एप्लीकेशन, इक्नोमिक्स तथा हिस्ट्री आदि के यहां विभिन्न कोर्सेस हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कोर्सेस चलाने की योजना भी बनाई है। 19891 में इस विश्वविद्यालय की नींव एक प्रदेशिक, राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के रूप में रखी गई थी। 1996 में इसे केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में लिया है। इसलिए अभी चार-पांच वर्ष ही हुए हैं लेकिन इसका प्रबंध ठीक से चलाने में पूरी सावधानी बरती गई है। केन्द्र सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई गफलत की कमी नहीं है। हर दृष्टि से पूरी सहायता दी जा रही है। नये कोर्सेस, नये-नये विषयों में इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप बनना चाहिए उसे बनाने की पूरी योजना है। कोई गफलत सरकार की तरफ से जान-बूझकर या अनजाने में नहीं हूई है। सरकार पूरी तरह से जागरूक है। इसके अतिरिक्त इसके प्रबंधन में भी अच्छे-अच्छे लोगों को लिया गया है। डॉ.आर.सी. मेहरोत्रा, श्री माता प्रसाद, जो बहुत अच्छे प्रशासक और यू.पी.एस.सी. के मैम्बर रहे हैं, डा. रमेश चंद्रा, जो बुदेलखंड के वाइस चेयरमैन रहे हैं तथा श्री हनुमनथप्पा आदि इसके बोर्ड में शामिल हैं. बड़े-बड़े लोग इसके बोर्ड में हैं इसलिए यह नहीं कहा जो सकता कि यह सरकार की तरफ से उपेक्षित है। संसद सदस्यों को भी इसके प्रबंधन मे रखा गया है। श्री डी.पी.सिंह, श्री पी.एल. शंखवार और श्री रामशखल जी भी इसके बोर्ड में शामिल हैं। कोशिश की जा रही है कि एक अच्छे प्रबंध समुदाय का रूप इसे दिया जाए। पैसे के मामले में भी सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था होती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी होती है जो अपने बोर्ड और स्टेच्यूट्स ऐक्ट के मुताबिक काम करती है। वह अपना काम ज्यादा सतर्कता और तेजी से करे इसका प्रयास किया जा रहा है लेकिन मैं यह भी कहूंगा कि इस संस्था को हाथ में लिए अभी केवल चार-पांच साल ही हुए हैं।

श्री आर॰ पी॰ गोयनका: सभापति महोदय, चार-पांच साल एक लंबा अरसा होता है और अभी तक केवल दो सौ छात्र ही इस यूनिवर्सिटी से इन सालों में निकले हैं। इस विश्वविद्यालय को दो सौ करोड़ रुपये दिए गए हैं। मैं यह नहीं कहता कि नहीं दिये गये हैं लेकिन ये दो सौ करोड़ रुपये कम पड़ते हैं। यदि आप यहां के वाइस चांसलर से बात करें तो आपको मालूम होगा कि यहां क्या-क्या कमियां हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, हमने इस संबंध में बात की है। जो बीस करोड़ रुपये दिये गये हैं उसमें से साढ़े चार करोड़ रुपये अभी तक खर्च नहीं हो पाए हैं। वहां क्या कमियां हैं इसकी जांच की चा रही है और इन कमियों को कैसे दूर किया जाए इसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त किया गया है। उनकी समीक्षा आने पर हम इस पर विचार करेंगे। इसके अतिरिक्त कुलपति से हमारा बराबर संपर्क बना रहता है।

श्री संघ प्रिय गौतम : सभापति महोदय, वैसे तो काफी हद तक मंत्री महोदय ने संतुष्ट करने

का प्रयास किया है लेकिन फिर भी मैं उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सारे भारत वर्ष में यह ही एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसके बारे में कमजोर वर्ग, अम्बेडकर के अनुयायिओं,दलित चातियों का यह कांसेप्ट है कि यह उनका विश्वविद्यालय है। वे इस पर गौरव और स्वाभिमान महसूस करते हैं। हर सरकार का दृष्टिकोण इन वर्गों के प्रति हमेशा सहयता का रहा है जिससे ऐसा लगता है कि ये उपेक्षित नहीं हैं, इन्फीरियर नहीं हैं। यह विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालयों से सुपीरियर हो इसके लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि ने स्वयं दिलचस्पी लेकर इसे ज्यादा धन दे दें और इसकी लुक अच्छी बना दें क्योंकि पी.जी.आई का लुक उसी रोड से जितना अच्छा दिखता है उतना इसका नहीं। पूर्व प्रश्नकर्ता ने ठीक ही कहा कि सड़क से इसका लुक अच्छा नहीं दिखाई देता। क्या मंत्री महोदय इस पर ध्यान देंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी : इसकी तरफ ध्यान देने का काम तो विश्वविद्यालय प्रशासन का है। वहीं अपना कंस्ट्रक्शन प्लान बनाते हैं, वही उसको स्वीकार करते हैं। हम तो जो । आवश्यक धनराशि उनको आबंटित करते हैं उसके लिए जिम्मेदार हैं। बाकी वह लोग अच्छा से अच्छा बनायें यह हम भी चाहते हैं। आपकी राय हम उन तक जरुर पहुंचायेंगे और हम भी चाहते हैं कि विश्वविद्यालय का भवन और परिसर अच्छा बने। लेकिन इसको बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नहीं होती। वह तो विश्वविद्यालय की निर्माण समिति और उसके अधिकारियों के विजन पर निर्भर करता है कि वह भवन का कैसा नक्शा बनाते हैं, कैसे क्या करते हैं। हम उस के लिए आवश्यक धनराशि जरुर देते है ।और देते रहेंगे।

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Mr. Chairman, I would like to make a request to the hon. Minister. Fortunately or unfortunately, I was a Board member of the Dr. Babasaheb Ambedkar University. I know what problems are faced by this University. My colleague, Mr. Sangh Priya Gautam, has rightly mentioned, all over India, people have very good feelings about this Central University because a special consideration of 50 per cent reservation is given for the SC and ST communities. Sir, the surrounding compound wall has not been constructed properly. The construction is very poor. There are openings at places. All sorts of elements including animals come and go through them to this side and that side.

Another thing is, there is an approach road. As rightly mentioned by the hon. Member, it is very difficult to reach the University premises. The creation of a post of engineer was not accepted. There is no experienced engineer to look after the compound construction and that area. There is no such post. Just one Executive Engineer has to look after the construction of the entire division, the maintenance of the entire University, planning and erection and even other activities. There is one Junior Engineer for electricity and connected

Departments. The fund which is allocated is very small. To expend even that, there should be an Engineer who will make the plan, estimate, etc. and execute the work. The Vice-Chancellor cannot do that. A senior person has to be appointed for that. Even in the Department created Cor Dr. Ambedkar Thoughts, one lecturer is there. There is no reader, no professor. When that is the position, how can the department run smoothly? I would like to know from the hon. Minister why the post of head of the department, the post of professor and the post of reader are not filled up. Even in other departments, posts are not filled orcreated. For example, in the Software Department, there is only one instructor. How can the University run smoothly without the necessary appointments? There is no accommodation for the staff; there is no accommodation for the students. Where will they go for staying? The University is not in the heart of the city. It is far away from the city on the Rae Bareily Road. There are a lot of difficulties. Mr. Chairman, Sir, if the hon. Minister docs not look into the matter seriously, the University, a Central University, created by this Parliament, in the name of a great leader of this country, will die very soon.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति जी, यह बिल्कुल सच है कि इस विश्वविद्यालय पर तमाम लोगों का विशेष ध्यान है और होना भी चाहिए। यह हमारे देश के एक बड़े नेता के नाम से बना है और उनके कामों के आधार पर वहां वहां अध्यन हो, उन्होंने जो देश को दिशा दी उसका भी वहां बिश्लेषण हो, अनुसंधान हो, इस सब के लिए ही यह बनाया गया है। इसलिए जब से इसका प्रबंध केन्द्रीय सरकार के पास है हमने अपनी तरफ से उनको 48 स्थान अध्यापन के लिए दिए हैं। 11 प्रोफसर, 15 रीडर और 30 लेक्चरर, यह हमने उनको सेंक्शन कर दिए हैं। वे उनको कितना भर पाए, कितना नहीं भर पाए, उसकी रेकूटमेंट की प्रक्रिया में क्या कठिनाई है इसका विचार तो वही करते हैं। विश्वविद्यालय स्वायत है इसलिए हम उनको मजबूर नहीं कर सकते कि आप तत्काल भरिए, किसे रखिए, किसे न रखिए। यह बात सही है कि वहां पर प्रोफेसर के 11 स्थान सेंक्शन किए हैं, रीडर के 15 और लेक्चरार के 30 स्थान सेंक्शन किए है। 48 में से वे अभी केवल 13 स्थान भरे गए हैं। अब हम उनसे यह जानकारी लेंगे कि वह क्यों देरी कर रहे हैं। हमारी तरफ से कोई देरी नहीं हुई है। हमने पूरा पैसा दिया हुआ है। आफिसर ग्रेड के हमने 14 ऑफिसर के स्थान सेंक्शन किए है। आप देख रहे हैं वहां पर 180 लड़के हैं। उनके लिए 48 पोस्ट अभी तक हमने सेंक्शन की हुई हैं। तो टीचर और स्टुडैंट के बीच यहां पर जो अनुपात है यह कहीं और देश में है नहीं।

रजिस्ट्रार, फाइनेंस आफिसर, डिप्टी फाइनेंस आफिसर, रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट फाइनेंस आफिसर, लाइब्रोरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सिक्युरिटी आफिसर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, यह सब हमने सेंक्शन किये हुए हैं। आफिसर ग्रेड बी भी सेंक्शन किये हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सेंक्शन नहीं किये हों लेकिन यह भी सच है कि वहां रजिस्ट्रार का पद खाली है ,

फाइनेंस आफिसर का पद खाली है, डिप्टी फाइनेंस आफिर का पद खाली है, डिप्टी रजिस्ट्रार का पद खाली है। यह विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों की कमजोरी है कि इन स्थानों को वे भर नहीं पाए हैं। केन्द्रीय सरकार भर्ती नहीं करती है। हम उनसे बराबर आग्रह कर रहे हैं और इस बारे में जांच भी कर रहे हैं कि क्या कठिनाइयां हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। हम उनको सलाह दे सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं मगर काम तो उन्हें करना पड़ेगा। विश्वविद्यालय के प्रबन्धकों को इस के अन्दर सरकार की तरफ से पूरी सहायता है। विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट को, कुलपति को, बाकी लोगों को भी ध्यान रखना चाहिऐ कि वह किस महान और श्रेष्ठ व्यक्ति के नाम से चलने वाले विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि वह लोग भी सदन की इस बात का ध्यान रखेंगे। हम तो पूरे तौर पर इसमें प्रयत्नशील हैं और रहेंगे।

VEN'BLE DHAMMAVIRIYO: Sir, the Hon. Minister, while answering the question, has stated that the Government has given a lot of money.

MR. CHAIRMAN: Ven'ble Dhammaviriyo, no more questions. Shri Pranab Mukherjee.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: Mr. Chairman, Sir, the hon. Minister has stated in the statement that the university started in 1989 as a State University, and the academic session started in 1997. Therefore, when it was a State University from 1989 to 1997, no activity was there, no admission, nothing of the kind. As per the Minister's statement, the actual academic session started from 1997. Out of 136 posts, 118 posts were filled up. He has given the breakup for four years. I would like to know as to what the status of the university between 1989 and 1997 was. Secondly, the question is, a University is declared as a Central University through an Act of Parliament, and we have also ensured that Parliament has an institutional representation in the Board of Management, either in the Court or in the Council, like the JNU, like the Vishwa Bharati University or like the Banaras Hindu University. The whole idea is that when the Central Government is taking the responsibility of funding it, when the Central Government is taking the responsibility of running the Central University, by passing an Act of Parliament, they should also ensure that all these things are complied with. Therefore, I do fully appreciate the hon. Minister's gesture that he would not like to interfere with the academic activities of the university. But surely, if the posts are not filled up, if the money granted to the university for the purpose, is not being properly utilised, if you step in, it would not amount to interference with the academic activities of the university. It is the actual responsibility of the Government of India to ensure that these administrative Acts are being complied with. I would like the hon. Minister

not to interfere with the academic activities. But in regard to the non-academic activities, especially with regard to maintenance and development, surely, the Government of India is accountable to this House and to the other House, as the University was established by an Act of Parliament. In this connection, it has been stated that Rs. 20.98 crores have been sanctioned till date, out of which even Rs. 4.5 crores have not yet been spent. Do I assume that the entire amount is on capital account or does it include both capital account and revenue account? I would be grateful if the hon. Minister can give the break-up on this count.

डा. मुरली मनोहर जोशी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसमें वजन है। जब राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय बनाया था वह चार पांच साल तक इस के बारे में प्रगति की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए। इसीलिए केन्द्रीय सरकार ने उसको लिया। जमीन के झगड़े थे, जमीन ट्रास्फर कैसे करें, कहां करें, शुरू में ऐसी समस्याएं होती हैं और राज्य सरकार उसका ठीक प्रबन्ध नहीं कर पा रही थी। इसीलिए यह देख कर केन्द्रीय सरकार ने संसद के माध्यम से उसका अधिग्रहण किया और एक नया विश्वविद्यालय बनाया।

श्री रमा शंकर कौशिक: वहां की सरकार ने आपसे निवेदन किया था। (व्यवधान)

डा. मुरली मनोहर जोशी : पैसा भी नहीं था, नहीं चला पा रहे थे, इसका मतलब यह है कि सब प्रकार की कठिनाइयां थीं, इसलिए ले लिया गया और लेने के बाद 1995 से एक तरह से उस विश्वविद्यालय का काम शुरु हुआ। 1989 से 1995 तक कोई वाइसचांसलर, कोई यह चीज, कोई व्यवस्था, इस तरह को कोई चीज वहां नहीं थीं। 1995 से काम शुरु हुआ, 1996में उसका नोटीफिकेशन हुआ, 1997 से शैक्षिक सत्र-अब एक साल में आप देखिए, 1996 में नोटीफिकेशन हुआ, 1996 में एकेदमिक सेशन शुरू हो गया। तो यह कहना कि वहां कुछ भी नहीं हुआ, यह ठीक नहीं है। लेकिन उसमें अनेक प्रशासनिक कठिनाइयां हैं और प्रशासनिक कठिनाइयां इस बीच में भी आती रही हैं। मैं उनका विस्तार में उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में आपस में मतभेद था। कुलपति में और बोर्ड आफ मैनेजमेंट में मतभेद था और उसके बारे में विजिटर के पास भी शिकायतें गयीं। विजिटर ने फिर हमको आदेश दिया कि आप उसमें जांच कराइए। हमने जांच कराई। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि क्या कठिनाइयां हैं, क्या नहीं है। सरकार पूरी तरह से इस में ध्यान दे रही है और ध्यान देती रहेगी। इसमें आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। जहां तक पैसे का सवाल है इसमें केवल दो करोड़ रुपया नानप्लान का है। बाकी सारा रुपया प्लान का है। वह इसीलिए है। दूसरा, कंस्ट्रक्शन कराना, उसमें प्लान पास होना, कंस्ट्रक्शन के लिए शरुआत होना-एक दिन में भवन नहीं बन जाता है। उसके लिए समय लगता है। बहुत से ऐसे स्थान हैं जो इनसे भी पहले से शुरू हुए हैं लेकिन अभी भवन नहीं बन पाए हैं। सीपीडब्ल्यूडी के अपने नार्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज के अपने तरीके हैं। उसमें से रास्ता निकालकर सारा काम होता है। तो यह चिंता की बात नहीं है मेरे लिए कि

पांच साल में केवल दो सौ लड़के ही आ पाए हैं। चिंता की बात यह है- विश्वविद्यालय की प्रगति, पोस्ट्स का भरना और विश्वविद्यालय के अंदर सरकार की तरफ से किसी तरह की कमी न होना। इसकी हम ज्यादा चिंता करते हैं। पोस्ट्स क्यों नहीं भरी गयीं-उसमें भी हम इंटरफेयर नहीं करते क्योंकि उनके अपने नियम है अपने एक्शन स्टेट्यूट्स है। वे एडवटाइज करते है। उस के बाह फिर भर्ती के लिए इंटरवयु करते हैं। अब क्वालीफाइड आदमी नहीं मिला। आजकल यह भी एक कठिनाई हो रही है कि बहुत से विषयों में जैसी क्वालीफिकेशन चाहते हैं, जैसे नार्म्स है उनके मुताबिक कई बार लोग नहीं मिलते हैं। उससे डिले होती है। नये विश्वविद्यालय में जैसा अभी बताया गया कि आवास नहीं है, मकान नहीं है, शहर से दूर है इसलिए बाहर से आने वाले लोग दिक्कत करते हैं। इन कठिनाइयों को पूरा करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं उसका विकास जल्दी से जल्दी हो और मैं इस सदन को बराबर भरोसा दिलाता हूं कि इस विश्वविद्यालय की तरफ हमार पूरा ध्यान है क्योंकि यह एक नया विश्वविद्यालय है और हम इसे एक अच्छी बुनियाद पर कायम करना चाहते हैं।

प्रो. रामगोपाल यादव : श्रीमन्, विश्वविद्यालय शब्द इतना व्यापक है और जब यह शब्द दिमाग में आता है तो हर व्यक्ति के मन में उसका एक कन्सेप्शन होता है। लेकिन जब यह पता चलता है कि इस विश्वविद्यालय में 170 लड़के हैं तो लगता ही नहीं कि यह विश्वविद्यालय है। चार साल पहले जो लोग हाईस्कूल, इंटर कालेज और डिग्री कालेज भी खोलते हैं उनमे भी हजारों लड़कों से कम नहीं होते। मैं माननीय मंत्री जी से दो हिस्सों में सवाल करना चाहूंगा। एक तो स्वायत्तशासी संस्था के नाम पर ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी बहुत लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं जबकि मेरा अपना मत यह है कि जिस दिन हिंदुस्तान के मानव संसाधन मंत्री चाहेंगे, एक महीने के अंदर सारी वेकेंसीज भर जाएंगी क्योंकि आखिर वाइस चांसलर को कौन एप्वाइंट करता है। भले ही किसी के नाम से एप्वाइंट होता हो लेकिन सारी दुनिया जानती है कि सब कुछ मंत्रालय से होता है। इस लिए यह नहीं है कि आपका कोई नियंत्रण नहीं है। कोई वाईस चांसलर मनमाने तरीके से काम नहीं कर रहे है ।ऐसा भी नहीं है कि सौ करोड़ की आबादी में क्वालीफाइड लोग न मिलते हो। एक-एक पोस्ट के लिए बीस-बीस क्वालीफाइड लोगों की लाइनें लगी होती हैं। जब आप एप्लाई नहीं करेंगे, जब वाइस चांसलर या प्रबंधन कहीं कोशिश नहीं करेगा, कोई वेकेंसी क्रीएट नहीं करेगा, कहीं से आवेदन नहीं मांगेगा तो श्रीमन, एप्वाइंटमेंट अपने आप नहीं हो सकते हैं।

दूसरा मैं यह जानना चाहूंगा कि जो आपने कोर्सेज वहां शुरू किए है ये कितने कोर्सेज हैं, कितनी सीट्स उनके लिए सैक्शन्ड हैं और उन सीट्स के हिसाब से स्टुडेंट्स और टीचर्स का रेशियो क्या है और क्या उस रेशियो के अनुसार आजकल टीचर्स वहां पर हैं?

डा. मुरली मनोहर जोशी : कोर्सेज मैंने पहल भी बताए इन्वारनमेंटल साइंसेज और इन्फोरमेशन साइंसेज हो गयीं । दो साल का एम.एससी. को कोर्स है। पहले तो यह बात है कि ये वहां पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं, अंडर ग्रेजुएट क्लासेज नहीं हैं जिनमें संख्या बहुत होती है। दूसरी बात यह है कि यह कोई

प्राइवेट स्कूल नहीं है कि जिसमें जितना चाहें भर्ती कर लें, चाहे जिसको रख लें, चाहे जब निकाल दें। यह नहीं होता है।

प्रो. रामगोपाल यादव : इसी लिए तो मैं सीट्स की संख्या पूछ रहा हूं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: विश्वविद्यालयों में ऐसा नहीं होता है। विश्वविद्यालयों को चलाने का अनुभव माननीय सदस्य को अभी करना होगा तब पता लगेगा। स्कूल चलाना और विश्वविद्यालय चलाना एक साथ नहीं है। तो इन्फारमेशन साइंसेज, हार्टिकल्चर, सेरीकल्चर ...(**व्यवधान**)

PROF. RAM GOPAL YADAV: I raise serious objection to this, Sir... *(Interruptions)...*

SHRI MD. SALIM: It is a Member's right. Joshiji is a renowned professor. *(Intcrrutpions)...* आप फिज़िक्स के प्रोफैसर हो सकते है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैंबर को सिर्फ स्कुल चलाने का अनुभव है और यूनिवर्सिटी चलाने का अनुभव नहीं है। इट इज़ वैरी अनफॉर्चुनेट, सर। ...(**व्यवधान**)

प्रो. रामगोपाल यादव : मुझे पोस्ट ग्रेजुएट चलाने का, एम.ए. क्लासेज़ को पढ़ाने का 20 साल से भी ज्यादा का अनुभव है।

डा. मुरली मनोहर जोशी : बिल्कुल अनुभव है। ...(**व्यवधान**) आपके अध्यापन के अनुभव...(**व्यवधान**)

प्रो. रामगोपाल यादव: आप मिनिस्टर हो गए, इसलिए आप प्रोफैसर हो गए यूनिवर्सिटी के मामले में। ...(**व्यवधान**)

डा. मुरली मनोहर जोशी: आपके अध्यापन के अनुभव पर मुझे कोई शक नहीं है। आप बहुत कुशल अध्यापक हैं।...(व्यवधान)

प्रो. रामगोपाल यादव: यह कोई बात नहीं है। आप अपनी इंकंपीटेंसी को दिखाने के लिए यह कहेंगे

श्री मोहम्मद सलीम: मंत्री जी को बहुत कुछ मालूम है, इसलिए इसका मतलब यह नहीं है कि मैंबर को पूछने का राइट नहीं है। ...(व्यवधान)

प्रो. रामगोपाल यादव : अपनी अक्षमता को दिखाने के लिए यह कह कर काम नहीं चल सकता है।...(व्यवधान)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, it is a reflection on the Member. It should be expunged.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: तो एनवायरनमेंटल साईंसेज़, इसमें प्रथम सेमेस्टर में 20 लोगों की ...(**व्यवधान**)

श्री मोहम्मद सलीम : आप एचआरडी मिनिस्टर हैं ...(**व्यवधान**) अध्यापक हैं और सदस्य सवाल पूछ रहे हैं। आप कहते हैं कि अनुभव क्या है, विश्वविद्यालय चलाने का अनुभव क्या है। वह बी.आर. अंबेडकर यूनिवर्सिटी की हालत देख कर समझा जा सकता है।...(व्यवधान) एचआरडी मिनिस्टर, क्या योग्यता है विश्वविद्यालय चलाने के लिए...(व्यवधान)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: और 20 के 20 इसमें दाखिल हैं। इन्फर्मेशन साइंस में 20 छात्रों के लिए भर्ती की आवश्यकता है और बीस के बीस भर्ती हैं। हॉर्टीकल्चर में 20 ...(**व्यवधान**)

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Sir, you must protect the rights of the Members. He should withdraw his words. *(Interruptions)...*

MR. CHAIRMAN: I think the hon. Minister did not mean any such aspersion. *(Interruptions)...!* hope he doesn't want to cast any aspersion on him.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : मैंने तो कहा कि उनके अध्यापन पर तो मुझे बहुत नाज है। वह बहुत अच्छे अध्यापक हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र : जब इन्होंने यह कहा कि एक विश्वविद्यालय में 2-3 साल में हजार से ऊपर विद्यार्थी होते है तो मंत्री जी ने यह कह दिया कि देखिए यह स्कूल चलाना अलग बात है और विश्वविद्यालय चलाना अलग बात है ...(व्यवधान) यह भाषा अच्छी नहीं है। हम समझते हैं कि संसदीय परंपरा के हिसाब से किसी मैंबर के सवाल पूछने पर मिनिस्टर हीन भावना से ग्रसित हो करके जवाब दे या ...(**व्यवधान**)

श्री सभापति: हीन भावना नहीं चाहते ...(**व्यवधान**)

श्री जनेश्वर मिश्र : हीन भावना पैदा करें, यह दोनों गलत है। ...(**व्यवधान**)

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : हम इनका बहुत आदर करते हैं।

श्री सभापति : आप की बात ठीक है।

डॉ. मुरली मनोहर जोशी : इन्फोर्मेशन साईंसेज़ में भी 20 छात्र हैं, हॉर्टीकल्चर में भी 20 की कैपेसिटी है और बीस के बीस छात्र हैं, सेरीकल्चर में भी बीस के बीस छात्र हैं, ह्युमैन राइटस में 13 छात्र हैं, इसमें कम हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस में भी 20 की कैपेसिटी है और बीस छात्र हैं, इकोनोमिक्स में कैपेसिटी है लेकिन छात्र कम आए हैं, चार छात्र है, हिस्ट्री में कैपेसिटी हैं, लेकिन छात्र बहुत कम आए हैं, चार छात्र हैं...(**व्यवधान**)

प्रो. रामगोपाल यादवः इन सब्जैक्ट्स में टीचर हैं या नहीं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशीः हां, सर सब टीचर्ज़ हैं। 13 टीचर हैं और 48 लोगों की सैंक्शंड पोस्ट्स हैं 168 लड़कों के लिए 13 टीचर्ज़ भी हिन्दुस्तान के किसी भी नॉर्म से अधिक हैं, लेकिन 12 फैक्लटी यहां एडज़ंक्ट फैक्लटी है, विज़िटिंग प्रोफेसर्ज हैं। इसलिए 25 लोग नियुक्त हैं। अध्यापकों की संख्या में कोई कमी नहीं है। 168 छात्र हैं। इसलिए आपने अगर मेरा पहला उत्तर सुना होता तो मैंने तभी बता दिया था कि हमने 48 पोस्ट्स सैंक्शंड की है जिसमें से 13 इन्होंने भरी हैं। 25 आस-पड़ोस के विश्वविद्यालयों से बुलाते हैं और इस तरह से फैक्लटी में कोई कठिनाई नहीं है। दिक्कत है तो छात्रों के आने में दिक्कत है। जैसा सम्मानित सदस्य ने बताया था कि होस्टल की कमी के कारण छात्र कम आते हैं। भवनों की कमी होने के कारण से कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। और जैसे-जैसे भवन बढ़ेंगे, छात्रवास बढ़ेंगे, वैसे-वैसे कैपेसिटी भी बढ़ेगा। विश्वविद्यालय ग्रो करते हैं।

Vacant posts of teachers in engineering colleges

*442. SHRI SANJAY NIRUPAM: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 10,000 teachers' posts are going abegging in engineering colleges around the country;

(b) if so, since when these posts are lying vacant and what are the reasons therefor; and

(c) what steps Government have taken to fill up the vacant posts and by when?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLIMANOHAR JOSHI): (a) to (c) It is estimated that shortage of teachers of this order of magnitude exists in engineering colleges at various levels. There has been a major expansion of the technical education system in the recent past and it takes time for recruitment of sufficient number of teaching personnel as it is a time consuming process. Filling of vacancies is a dynamic and continuous process. One of the main reasons for vacancies is the relative disinclination of competent professionals to join the teaching profession in view of generally better opportunities available elsewhere. Government has taken various steps, viz revision of pay scales along with better service conditions, launching of Early Faculty Induction Programme to attract young talents to the teaching profession; and operation of various faculty development programmes like, quality improvement programmes, continuing education programme, etc. to retain existing teaching faculty.